

उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों के 4% आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

27 जनवरी, 2023 को उत्तराखण्ड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में चार प्रतिशत क्वॉटा आरक्षण देने के लिये राज्य सरकार अध्यादेश ला रही है। न्याय विभाग ने अध्यादेश लाने को मंजूरी दे दी है।

प्रमुख बिंदु

- विभाग के अधिकारियों के मुताबकि पूर्व में 4 प्रतिशत क्वॉटा आरक्षण का शासनादेश था, लेकिन 2013 में हाईकोर्ट ने इस शासनादेश को रद्द कर दिया था।
- खेल मंत्री रेखा आर्य के मुताबकि प्रदेश के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ दिया जा सके, इसके लिये न्याय और कार्मिक विभाग से सहमति मिली गई है और इसके लिये नियमावली बनाई गई है।
- कैबिनेट के माध्यम से अध्यादेश लाकर या विधानसभा के माध्यम से इसे कानून बनाया जाएगा। इससे प्रदेश में खेल का और बेहतर माहौल बनेगा व खिलाड़ियों का भविष्य सुरक्षित होगा।
- खेल निदेशक जतिंद्र सोनकर ने बताया कि प्रदेश सरकार हरियाणा राज्य की तरफ पर उत्तराखण्ड में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता को 5400 ग्रेड पे पर सीधे नौकरी देने की तैयारी कर रही है। इसके लिये तैयार प्रस्ताव को वित्त और कार्मिक विभाग से मंजूरी मिली गई है।
- इसका शासनादेश जारी होते ही हरियाणा के बाद उत्तराखण्ड पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा।
- खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखण्ड को खेलभूमि के नाम से भी जाना जा सकेगा।